जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 49 संख्याः 255 प्रभात कोटा, शुक्रवार 28 जून, 2024 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

अठारहवीं लोकसभा का एजेण्डा निर्धारित हुआ सदन के पहले ही दिन

आमने-सामने टकराव की रणनीति बना ली है, सरकार व विपक्ष ने

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जून। मोदी सरकार और विपक्षी इण्डिया गठबंधन के बीच टकराव 18वीं लोकसभा की सबसे उल्लेखनीय बात है।

संसद के दोनों सदनों के लिए एजेण्डा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, लेकिन विपक्ष एक स्थगन प्रस्ताव रखकर मांग करेगा कि, नीट के अति महत्वपूर्ण और वर्तमान मुद्दे पर तुरंत बहस होनी चाहिए, जिसने देश को हिलाकर रख दिया है और लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

कल शुक्रवार है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है।

विपक्ष यह स्पष्ट करेगा कि, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट नहीं कर रहा है, लेकिन, वो सोमवार को इस पर बहस करना चाहता है।

माना जा रहा है कि, यदि नीट पर बहस की अनुमति नहीं दी गई तो विपक्ष सदन में भारी हंगामा कर सकता है। विपक्ष दोनों सदनों में स्थगन की स्थिति पैदा कर देगा और सदन का कामकाज नहीं होने देगा।

- हालांकि, परम्परा के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत अभिभाषण पर बहस करके धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना पहली प्राथमिकता होती है। पर, इस बार विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाना चाहता है, और आम जनता की सबसे बड़ी चिंता, ''नीट'' परीक्षा में पेपर लीक का मसला उठाना चाहता है।
- विपक्ष, तकनीकी दृष्टि बड़ी होशियारी से अभिभाषण का बायकॉट नहीं कर रहा है, बल्कि जनता को सबसे ज्यादा चुभने वाले मुद्दे पर सदन में बहस चाहता है।
- विपक्ष का कहना है कि, नीट पर बहस की उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। विपक्ष, अपनी इस रणनीति से लोकसभा का एजेण्डा सैट करना चाहता है।
- विपक्ष, सोमवार को संसद परिसर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर धरने पर भी बैठेगा।
- धरना सरकार द्वारा, ई.डी., सी.बी.आई. आदि जाँच एजेन्सियों का विपक्ष के नेताओं के खिलाफ खुला उपयोग करने के विरोध में आयोजित किया गया है। दिल्ली के मु.मंत्री केजरीवाल, झारखंड के मु.मंत्री हेमन्त सोरेन तथा, प.बंगाल के तीन कैबिनेट मंत्रियों की गिरफ्तारी सरकार की इस प्रतिशोध की रणनीति का उदाहरण है।

आज शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई विपक्षी इण्डिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी नेताओं ने तय किया कि, संसद में नीट का मुद्दा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्पष्ट है कि, विपक्ष अपना एजैण्डा सैट करना चाहता है और इस बात को अधिक बड़ा पॉइन्ट बनाना चाहता है कि, जो मुद्दे आम आदमी को प्रभावित करते हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाना चाहिए।

यह सब भविष्य के कथानक को कन्ट्रोल और मॉनिटर करने का भी प्रयास है।

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सोमवार को विपक्षी दल संसद भवन परिसर में महात्मा गाँधी की प्रतिमा के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की

कोटा, 27 जून (निसं)। कोचिंग सिटी में एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

यह कोचिंग छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी करने के लिए झारखंड से कोटा आकर दादाबाड़ी थाना इलाके में रह रहा था और 12वीं की पढ़ाई के साथ मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी भी निजी कोचिंग संस्थान से कर रहा था। सुबह जब छात्र ने परिजनों का फोन नहीं उठाया तो परिजनों ने हॉस्टल मालिक को फोन किया। हॉस्टल मालिक द्वारा भी खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने

- झारखंड का 17वर्षीय ऋषित अग्रवाल 12वीं के साथ नीट-यू.जी. की भी तैयारी कर रहा था।

छात्र के शव को फंदे से उतार कर एम.बी.एस. अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया।

दादाबाड़ी थाना अधिकारी नरेश मीणा ने बताया कि, 17 वर्ष का ऋषित अग्रवाल झारखण्ड के देवघर का निवासी था। एफ.एस.एल. टीम ने भी कमरे की जांच पड़ताल की है। इसके संबंध में उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। परिजन झारखण्ड से कोटा के लिए रवाना हो गए हैं।

थाना अधिकारी ने बताया कि, प्रथम दृष्टया किसी तरह का कोई सुसाइड नोट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्पीकर ओम बिड़ला के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने भी ''एमरजैन्सी'' को भारत के प्रजातंत्र व संविधान का सबसे काला अध्याय बताया

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा, भारत के संविधान व प्रजातंत्र पर देश के अन्दर एवं बाहर से लगातार हमले हो रहे हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीसरी बार एन.डी.ए. की सरकार बनने के बाद नई लोकसभा को दिए गए अपने पहले संबोधन में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाए जाने को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया तथा कहा कि यह संविधान पर प्रत्यक्ष हमला था। यह स्पष्ट संकेत है कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ टकराव का रास्ता चुना है, बजाय देश के सम्मख मौजूद चुनौतियों पर आम राय बनाने के।

राष्ट्रपति ने कहा कि अब प्रयास किए जा रहे हैं कि संविधान को जनमानस का एक अंग बताया जा रहा है ऐसा लगता है कि यह लोकसभा चुनाव के दौरान और शपथ ग्रहण के दौरान इंडिया गठबंधन द्वारा संविधान का मुद्दा उठाने पर भाजपा को जवाब दे।

- जैसा कि विदित ही है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, सरकार तैयार करती है तथा यह सरकार की सोच व मन्तव्य का सूचक होता है।
- राष्ट्रपति ने विपक्ष की प्रतिस्पर्धा करने की सोच पर टिप्पणी की और कहा, प्रतिस्पर्धात्मक सोच के कारण, देश में प्रजातंत्र कमज़ोर पड़ता है।
- ''पिछले कई दशकों से अस्थिर सरकारों का दौर सा आया था देश में, और इस कारण से आर्थिक व समाजिक सुधार व अन्य आवश्यक निर्णय नहीं लिये जा सके थे।
- पर, अब जनता ने अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करते हुए, अस्थिर सरकारों की स्थिति पर रोक लगा दी है।

राष्ट्रपति का भाषण मौजूदा सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति मुर्मू अभिभाषण मोदी सरकार के इरादों की अभिव्यक्ति है। एक दिन पहले लोकसभा स्पीकर ने आपातकाल के खिलाफ दो मिनट का मौन रखवाया था। इससे जाहिर है कि मोदी सरकार ने विपक्ष के प्रति आक्रामक रूख अपनाया है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि, कुछ माह में भारत बतौर गणतंत्र 75 वर्ष पूरे कर लेगा। देश के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई?

विदेश मंत्री ने 2023 की धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी करते हुए तीखी टिप्पणियां कीं, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जून। भारत में धर्मान्तरण विरोधी कानूनों, हेट स्पीच तथा अल्पसंख्यक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों के विध्वंस के बढ़ते मामलों पर अमेरिका ने एक बार फिर चिंता जतायी है।

भाजपा नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के अभी तीन हफ्ते पहले ही सत्ता में लौटी हैं, लेकिन इस दौरान साम्प्रदायिक मोर्चे पर भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। इस अवधि में मॉब लिंचिंग, हिंसा और कथित हेट क्राइम्स के कई प्रकरण सामने आए। जैसी कि खबर मिली है, छत्तीसगढ़ में दो अलग-अलग घटनाओं में चार जनों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक और गुजरात में एक जने की अकारण हत्या कर दी गई।

बकरीद पर देश के कई हिस्सों में मुसलमानों को निशाना बनाने और साम्प्रदायिक असंतोष की खबरे थीं।

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में साम्प्रदायिक हिंसा मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, सिखों पर, दलितों पर, यहूदियों पर, आदिवासियों पर, अनुपात से कही ज्यादा भारी पड़ती है।

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वर्ष 2023 की रिलीजस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत के ईसाई समुदाय ने बताया था कि भारत में स्थानीय पुलिस समर्पित लोगों की भीड़ ने धर्मान्तरण गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उनकी प्रार्थना में व्यवधान उत्पन्न किया अथवा उग्र भीड़ जब उन पर हमला कर रही थी, तब पुलिस मूक दर्शक बने खड़ी रही। बाद में पुलिस ने धर्मान्तरण के आरोपों में पीड़ितों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट में मणिपुर की जातीय हिंसा का भी जिक्र है और उसमें समान नागरिक आचार संहिता, धर्मान्तरण को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों और नए आपराधिक कानूनों सहित प्रधानमंत्री के लीगल फ्रेमवर्क को लेकर आलोचनात्मक विचार हैं।

मई माह में भी, भारत ने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) की ऐसी ही एक रिपोर्ट को खारिज़ कर दिया था, इस रिपोर्ट में भाजपा पर ''भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियां पुनः लागू करने'' का आरोप लगाया था और आरोप लगाया था पार्टी पक्षपाती राजनीतिक एजेन्डा लागू करने वाली है''। यूएससीआईआरएफ ने यह भी आरोप लगाया था कि भारत सरकार ''साम्प्रदायिक हिंसा'' से निपटने में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महिला शिक्षक को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ दिया जाए

जयपुर, 27 जून (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने फरवरी, 1992 में नियुक्त हुए महिला शिक्षक को राहत देते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि, उसके सेवाकाल की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से कर समस्त सेवा परिलाभ दिए जाएं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश संतोष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते

- राजस्थान हाई कोर्ट ने फरवरी 1999 में नियुक्त महिला शिक्षक संतोष की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।

हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि, याचिकाकर्ता संतोष की नियुक्ति फरवरी, 1992 में हुई थी। इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश का वेतन नहीं दिए जाने का निर्देश दिया था। जिसके चलते याचिकाकर्ता की सेवा में ब्रेक माना गया और उसे एक जुलाई से सेवा में नियमित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'क्या ओ.एम.आर. शीट के बारे में शिकायत करने के लिए कोई समय सीमा है'

सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल टैस्टिंग एजेन्सी को नोटिस जारी कर पूछा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जून। सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को एक याचिका पर नैशनल टैस्टिंग एजेन्सी (एन.टी.ए.) से जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 5 मई 2024 को जो नीट-यू.जी. 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी उसके लिए प्रयुक्त ओ.एम.आर. शीट में अंकों के गणना असंगत की गई है।

न्यायाधीश मनोज मिश्रा व न्यायाधीश एस.वी.एन. भट्टी की अवकाशकालीन बैंच ने एन.टी.ए. को नोटिस जारी किया और उससे जवाब मांगा है कि नीट-यू.जी. 2024 की परीक्षा से संबंधित ओ.एम.आर. शीट पर दर्ज अंकों की गणना को लेकर शिकायतें देने की एक समय सीमा निर्धारित की जाए। अदालत ने इस याचिका को भी पहले से इस मसले पर लम्बित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया, जिन पर अब आगामी सुनवाई 8 जुलाई 2024 को होगी।

कोर्ट ने संक्षिप्त आदेश में कहा कि

- जस्टिस मनोज मिश्रा और एस.वी.एन. भट्टी की वकेशन बैंच ने एक लर्निंग ऐप ज़ायलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर यह नोटिस दिया है। यह याचिका 8 जुलाई को सुनी जाने वाली याचिकाओं के साथ ही सुनी जाएगी।
- बैंच ने लर्निंग ऐप द्वारा आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर करने पर भी सवाल किया। यह आर्टिकल मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बैंच ने पूछा कि, इस मामले में लर्निंग ऐप के कौनसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
- एन.टी.ए. द्वारा नीट-यू.जी. परिक्षार्थियों का ओ.एम.आर. शीट अपलोड़ की गई है, पर, कई परिक्षार्थियों को उनकी ओ.एम.आर. शीट नहीं मिली है।

क्या ''हम यह जानना चाहते हैं कि ओ.एम.आर. शीट्स उपलब्ध कराने के लिए कोई निश्चित सीमा निर्धारित की हुई है। फिलहाल हम इसे टैग करेंगे। एन.टी.ए. ने इस पर निर्देश ले।''

मामले की सुनवाई के शुरुआत में ही न्यायाधीश मिश्रा ने याचिकाकर्ता ज़ाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड-लर्निंग ऐप की तरफ से कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठ वकील आर. बसंत से पूछा कि वे आर्टिकल 32, जो मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए है का उपयोग कर शीर्ष अदालत में कैसे पहुँचे। मौलिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी ने ओम बिड़ला से भेंट की

नयी दिल्ली, 27 जून (वार्ता)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को सदन के अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की।

राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल भी था। गांधी की बिरला से यह भेंट लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई। इस दौरान विपक्ष के कई अन्य सांसद भी मौजूद रहे। इन सांसदों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरद

- नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी ने ओम बिड़ला से भेंट की, उनके साथ विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधिमण्डल भी था।

की सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती, द्रविड मुनेत्र कषगम की कनिमोझी, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, और कांग्रेस के गौरव गगोई, के. सुरेश, के. सी. वेणुगोपाल और शशि थरुर तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्य शामिल रहे।

लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद गांधी की बिरला के साथ पहली शिष्टाचार भेंट थी।

आडवाणी को एम्स से छुट्टी मिली

नई दिल्ली, 27 जून। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवानी को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें बुधवार रात दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। इससे पहले अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि, भाजपा के दिग्गज नेता की हालत स्थिर है और विशेषज्ञों की एक टीम उनकी जांच कर रही है। 96

- 96 वर्षीय पूर्व उप प्रधानमंत्री को बुधवार रात करीब 10.30 बजे दिल्ली एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था।

वर्षीय पूर्व उप प्रधानमंत्री को बुधवार रात करीब 10.30 बजे दिल्ली एम्स के पुराने प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया।

गौरतलब है कि, आडवानी उम्र संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आमतौर पर डॉक्टर उनका घर पर ही जांच करते हैं, लेकिन बुधवार रात उन्होंने पेशाब में संक्रमण की शिकायत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हम जो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं- मुख्यमंत्री भजनलाल

88 लाख से अधिक पैन्शनरों के बैंक खातों में 1037 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधी हस्तांतरित, मु.मंत्री ने लाभार्थियों से संवाद किया

झुंझुनूं, 27 जून (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि, सभ्य एवं विकसित समाज सभी वर्गों के विकास के लिए संवेदनशील रहता है। सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन जरूरतमंद को आर्थिक संबल देती है, साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़े रखती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाने के साथ ही पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि, वृद्धजन, एकल नारी, दिव्यांगजनों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है तथा इनके सामाजिक सुरक्षा के आवरण को कमजोर नहीं होने देगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर केशव उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के खेल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि की राशि हस्तान्तरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर प्रदेश के 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1 हजार 37 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तान्तरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के जरिए जरूरतमंदों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री ने खेल मैदान में अशोक के पौधे का रोपण भी किया।

- मुख्यमंत्री ने बताया कि, राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्ष पैन्शन योजना को एक हजार रूपए से बढ़ाकर 1150 रूपए कर दिया है तथा इसमें चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी। संकल्प पत्र का हर वादा पूरा किया जाएगा।
- पैन्शन राशि बढ़ाए जाने पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।
- कार्यक्रम का आयोजन झुंझुनूं के केशव उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के खेल मैदान में आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर पैन्शन राशि हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झुंझुनूं में राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पैंशन कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत व पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गदा भेंट की।